(b) The high yielding varieties have been extensively used in the firstline demonstrations and have been adopted by the farmers on a large scale.

देश में भूकंप के कारण हुई हानि

4081. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20 अक्तूबर, 1991 को और उसके बाद भूकम्प के झटके महसूस किये गये थे ;

(ख) इन झटकों के कारण संपत्ति, फसल तथा पशुधन को अनुमानतः कितनी हानि हुई ;

(ग) प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में कितने लोग मारे गये, कितने घायल हुए और कितने बेघर हो गए ;

(घ) प्रत्येक प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा केन्द्र से कितनी सहायता की मांग की गई और वास्तव में उन्हें कितनी धनराशि दी गई ;

(ङ) केन्द्रीय दलों ने इस संबंध में किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया ;

(च) केन्द्रीय दलों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

(छ) भूकम्प पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए अन्य स्रोतों से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ज) विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकार द्वारा राहत के संबंध में क्या उपाय किये गये हैं ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1991 के भूकम्प से उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में काफी हानि हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कुछ छोटी-मोटी हानि की सूचना दी है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू व काश्मीर तथा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र जहां इस भूकम्प के झटके महसूस किए गए थे, किसी क्षति की सूचना नहीं दी है। अक्तूबर, 1991 के भूकम्प के कारण उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई क्षति का ब्यौरा अनुबंध में है। (देखिए परिशिष्ट 162, अनुपत्र संख्या 8) 20.10.91 के बाद भारत में महसूस किए गए भूकम्प का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इन भूस्पंद से किसी क्षति की सूचना नहीं मिली है। [देखिए परिशिष्ट 162, अनुपत्र संख्या 82]

(घ) से (च) उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत और पुनर्वास उपायों के लिए 152.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। राहत उपायों के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा।

(छ) और (ज) गैर-सरकारी एजेंसियां भारतीय रेडक्रास सोसाइटी, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अपने चैनलों से राहत सामग्रियाँ भेज रही हैं। भूकम्प पीड़ितों के राहत के लिए विभिन्न स्रोतों से दी जा रही सहायता के ब्यौरे एक स्थान पर उपलब्ध नहीं है।

Direct and indirect subsidy to farmers

4082. SHRI PRABHAKAR B. KORE:
PROF. I. G. SANADI:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what was the quantum of subsidies, both direct and indirect in the sale of pesticides, fertilizers, support prices for foodgrains, energy supply, water supply for agriculture in the year 1960, 1970, 1980 and 1990;

(b) whether there is any indication that these have benefited the weaker sections specially the landless, small and marginal farmers and if so, details thereof;

(c) whether it is a fact that there have been similar subsidies for supply of seed of High Yielding Varieties and if so, details thereof;

(d) whether these subsidies are proposed to be given to support Organic Farming or sustainable agriculture in the country alongwith strong R and D support and Demonstration Farms etc.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Subsidy both direct and indirect, to farmers, for various inputs, is given through Central and State scheme, and through the price of these inputs. No comprehensive records are maintained obout the quantum of such subsidies.

(b) No detailed studies of the exact benefit of the direct and indirect subsidies on landless, small and marginal farmers is available.

(c) The details of the subsidy on seeds under some Central programmes is at Statement. (See below)

(d) There is no Central Subsidy scheme for Organic Farming or sustanable agriculture.

Statement

Subsidies for supply of seed of High Yielding Varieties

Item	Pattern of Assistance
Wheat	Rs. 200/- per quintal
Rice	Rs. 200/- per quintal
Maize & Millets	Rs. 400/- per quintal
Cotton	Rs. 400/- per quintal for acid delinted and Rs. 300/- per quintal for mechanically delinted seeds.

Refund of central excise duty on diesel

4083. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a scheme to refund Central Excise on diesel to the fishermen was sanctioned by Government in 1990-91;

(b) if so, the amount of refund actually paid upto December, 1991 to fishermen in Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra;

(c) the share of the Union and the State Governments respectively in the above refund;

(d) whether Government have received any request from these State Governments to continue the scheme after June, 1991; and

(e) if so, the decision taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) and (b) Yes, Sir. The Central Sponsored Scheme on Reimbursement of Central Excise Duty on HSD oil used by Fishing Vessels, below 20m length was sanctioned and implemented through Maritime State/UT Governments including Government of Maharashtra during 1990-91 (from 1-10-90 onwards). Inland